भारद्वाज) : (क) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में योजना आयोग को अभी अपने आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप (1992-97) तथा वार्षिक योजना (1992-93) के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Rural Poverty alleviation schemes

793. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that planners have suggested the merger of all the rural poverty alleviation schemes into one integrated one;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) what would be the financing pattern and employment generation targets?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) The Planning Commission has been suggesting the merger of all rural poverty alleviation schemes into one, for the integrated development of an area. This is based on the premise that decentralised planning and implementation of these schemes will make a better impact on the problem of poverty.

(b) The details of this approach are being worked out and will be included in the Eighth Five Year Plan Document.

(c) Does not arise.

Enactment of All India Agricultural Marketing Board Act

@794. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to enact an All-India Agriculture Marketing Board Act with a view to end the exploitation of farmers in the country;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) by when the proposed Act is likely to be implemented and to what extent the farmers are likely to be benefited therefrom?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) to (c) The State Governments are empowered to legislate in this matter and most of the States have enacted the Legislation. The Central Government does not propose a Central Legislation, but is pursuading the State Governments to enforce the provisions of the Acts effectively where they are already in existance and make the enactment where it does not exist.

गुजरात में नलकूपों का लगाया जाना

795. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत दो वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सहायता से कितने नलकूप लगाये गये हैं और उनका जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से कितने नलकूप काम कर रहे हैं और कितने निष्क्रिय पड़े हुए हैं;

(ग) निष्क्रिय नलकूपों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से इन जिलों में कितने नलकूप लगाये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) गुजरात में गत दो वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सहायता से 17 नलकूप

@Previously Unstarred Question 161, transferred from the 22nd November, 1991.

लगाए गए थे। जिलावार ब्यौरे निम्नलिखित है :–

जिला	नलकूपों की संख्या
राजकोट	2
कच्छ	12
अहमदाबाद	3
कुल:	17

(ख) काम कर रहे और निष्क्रिय पड़े नलकूपों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

जिला	नलकूपों की संख्या	
	कार्य कर रहे नलकूप	निष्क्रिय नलकूप
राजकोट	2	शून्य
कच्छ	6	6
अहमदाबाद	3	शून्य
कुल:	11	6

(ग) निष्क्रिय पड़े 3 नलकूपों को मार्च, 1992 तक और अन्य 3 नलकूपों को दिसम्बर, 1992 तक चालू कर दिये जाने की सम्भावना है।

(घ) 1991–92 में अहमदाबाद जिले में 3 नलकूप लगाए जाने की संभावना है।

ग्रामीण विकास के लिए अनुदान

796. **कुमारी आलिया :**
श्री अजीत जोगी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989–90 और 1990–91 के दौरान विभिन्न संस्थाओं और समितियों ने ग्रामीण विकास के लिए अनुदान हेतु "लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद्" को कितने आवदन पत्र भेजे थे;

(ख) उनमें से कितनी संस्थाओं और समितियों को कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया था; और

(ग) इन संस्थाओं ने प्राप्त अनुदानों में से कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) 1989–90 और 1990–91 के दौरान क्रमशः 2987 और 4836 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) वर्ष 1989–90 और 1990–91 के दौरान प्रत्येक वर्ष में 1156 संस्थाओं और समितियों को अनुदान दिया गया था। 1989–90 और 1990–91 के दौरान इन संस्थाओं और समितियों को क्रमशः 20.49 करोड़ रुपये और 17.34 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था।

(ग) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ने 1989–90 और 1990–91 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं के संबंध में इन समितियों को क्रमशः 17.47 करोड़ रुपये और 16.93 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की है।

Maintenance of land records in rural areas

@797. **SHRI SHIV PRATAP MISHRA:** Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that one of the reasons of unrest in rural areas is the lack of proper maintenance of land records;

@Previously Unstarred Question 145, transferred from the 22nd November, 1991.